अग्रवाल वुड्स के गोदाम में मुनीम ने ही करवाई थी डकैती

पुलिस ने मुनीम सहित चार आरोपियों को दौलतपुरा से गिरफ्तार किया

जयपुर,(कासं)। राजधानी के करणी विहार थाने से पांच सौ मीटर की दूरी पर अग्रवाल वुड्स गोदाम में व्यापारी को को बंधक बनाकर की गई 15 लाख 48 हजार की लूट उसके ही नौकर ने करवाई थी। पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में नौकर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि डकैती की पूरी योजना नौकर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। पुलिस फरार दो बदमाशों की तलाश में जुटी है। आरोपियों ने गोदाम में दो बार वारदात करने का प्रयास किया था, इस दौरान ज्यादा ग्राहक होने के कारण सफल नहीं हो पाए थे। इस वारदात का खुलासा करने में कांस्टेबल सागर

- **आरोपियों ने गोदाम में दो वार वारदात करने का प्रयास किया था।**
- **पुलिस फरार दो बदमाशों की तलाश में जुटी है।**

कड़वा की अहम भूमिका रही।

डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा ने बताया कि वारदात के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रामसिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इनमें इसमें एसीपी झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी, एसीपी वैशाली नगर आलोक कुमार, करणी विहार थानाधिकारी जयसिंह बसेरा, वैशाली नगर थानाधिकारी हीरालाल सैनी, चित्रकूट थानाधिकारी रामकिशन विश्नाई, कालवाड़ थानाधिकारी पन्ना लाल जागिंड और दौलतपुरा थानाधिकारी नरेन्द्र खींची को शामिल किया गया। पुलिस ने रात दिन काम कर आरोपियों को धर दबोचा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ओमप्रकाश उर्फ ओपी गुर्जर (20) गांव जोधुला विराटनगर, महेश मीणा उर्फ भोलू (28) निवासी सराय कलां मुण्डावर अलवर, विजय मीणा (22) निवासी पेजूका, कोटपूतली और रवि सोनी (23) निवासी खेतड़ी, झुंझुनूं है। राणा ने बताया कि पुलिस को सबसे पहले नौकर ओमप्रकाश गुर्जर उर्फ ओपी पर शक हुआ। वारदात के कुछ देर बाद ही पूछताछ के लिए उसे बुला लिया गया। इस दौरान वह बदल-बदल कर बयान दे रहा था। संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर पुलिस को उस पर और संदेह हुआ। सख्त से पूछताछ करने पर उसने वारदात करना कबूल कर लिया। उससे पूछताछ में वारदात में बदमाश सीताराम मीणा, प्रेम उर्फ लाला, रवि सोनी, महेश मीणा, विजय मीणा के शामिल होने का पता चला। इस पर पुलिस ने इन तीनों को जयपुर के दौलतपुरा से गिरफ्तार कर लिया। डकैती की योजना ओमप्रकाश गुर्जर ने अपने दोस्त सीताराम के साथ मिलकर की थी।

जयपुर पुलिस ने लूट के मामले में मुनीम सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

हरियाणा के दोस्त भी शामिल

नौकरी के दौरान शोरूम से लाखों रुपए की लेन-देन होने के बारे में उसे पूरी जानकारी हुई। इसके बाद उसने शोरूम पर डकैती डालने की प्लानिंग की। राजस्थान और हरियाणा के दोस्तों को अपने प्लान में शामिल किया। प्लानिंग के तहत विवेक के शोरूम में बैठने के कुछ देर बाद ही डकैती डाली गई। हथियार के दम पर 15.48 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए।

एसीपी झोटवाड़ा प्रमोद स्वामी ने बताया गिरफ्तार आरोपी मुनीम ओमप्रकाश करीब दो साल पहले पड़ोसी गांव मैड में परिचित की शादी में गया था। वहां उसकी मुलाकात आदतन बदमाश सीताराम मीणा से हुई। बातचीत के बाद दोनों में दोस्ती हो गई और मोबाइल पर एक-दूसरे से संपर्क में रहने लगे। करीब तीन महीने पहले सीताराम ने अपने साथी सोहन उर्फ सोनू के साथ मिलकर हार्डवेयर की दुकान पर हफ्ता वसूली के लिए फायरिंग की। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल को ओमप्रकाश गुर्जर को छिपाने के लिए दे दी। ओमप्रकाश ने फेसबुक पर पिस्टल के साथ वीडियो बनाकर अपलोड भी किए। करीब 15 दिन पहले ओमप्रकाश के गांव जाने पर सीताराम से मुलाकात हुई। बातचीत में सीताराम को बताया कि वह जयपुर में टिम्बर व्यापारी के यहां काम कर रहा है। उसके यहां रोज का करीब पांच लाख रुपए का काम-काज है। इसके बाद दोनों ने मिलकर डकैती की साजिश रची।

सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले

करणी विहार, वैशाली नगर, चित्रकूट, कालवाड थाना पुलिस सहित डीएसटी पश्चिम और साइबर टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। एफएसएल और फिंगरप्रिंट टीम को बुला कर साक्ष्य एकत्रित किए गए। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता के आधार पर बदमाशों को चिन्हित किया गया।

पिता के कहने पर बेटे को दी नौकरी

पिछले करीब 7 साल से ओमप्रकाश के पिता करणी विहार स्थित अग्रवाल वुड्स शोरूम के पास चाय की दुकान करते हैं। शोरूम पर चाय देने आने के दौरान उन्होंने कारोबारी विवेक अग्रवाल से अपने यहां बेटे को काम पर रखने की गुजारिश की थी। उनके कहने पर ओमप्रकाश को विवेक ने काम पर रख लिया। 2 महीने पहले नौकरी करने गांव से ओमप्रकाश जयपुर आ गया। धावास रोड पर किराए पर पिता के साथ रहने लगा।

खुद को भी बनवाया बंधक

डकैती में शामिल होने के बारे में ओमप्रकाश पर शक नहीं हो, इसलिए कैश लूटने के बाद मालिक के साथ उसे भी बंधक बनाया गया था। पड़ोसी के रस्सी खोलने के बाद हर गतिविधियों पर ओमप्रकाश नजर रखता रहा।

फर्जी नम्बर प्लेट बनवाई

सीताराम ने प्रेम उर्फ लाला, रवि सोनी, महेश मीणा और विजय मीणा को डकैती में शामिल किया। सीताराम ने अपने साथियों के साथ मिलकर डकैती डालकर फरार होने के सभी रास्तों की रेकी की। 2 सितम्बर को बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई। प्लानिंग के तहत शनिवार सुबह डकैती डालने के बाद बदमाश बाइक से सीताराम के घर चले गए।

छह हिस्सों में लूट की रकम बांटी

एडिशनल डीसीपी राम सिंह ने बताया बदमाशों ने डकैती की रकम को छह बराबर हिस्सों में बांट लिया था। प्रत्येक के हिस्से में 2.30 लाख रूपए आए थे। ऊपर के बचे रुपए को सीताराम ने अपना खर्चा बताकर रख लिया। ओमप्रकाश का हिस्सा भी सीताराम ने अपने पास रख लिया। गैंग के लोग पहले भी दो बार इसी गोदाम पर वारदात का प्रयास कर चुके थे, लेकिन विफल हो गए।

प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हो सकेगा कार्य

राजभवन में मंगलवार को राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में राजस्थान के तीन विश्वविद्यालयों और आई.एम.टी. गाजियाबाद के मध्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए।

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में मंगलवार को राजभवन में आई.एम.टी. गाजियाबाद एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तथा गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के मध्य खेल संस्कृति के विकास के संबंध में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर हुए। इसके अंतर्गत स्थानीय और पारम्परिक खेलों को पुनर्जीवित करने के साथ ही उच्च शिक्षण संस्थाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिए जाने पर कार्य होगा।

राज्यपाल ने इस अवसर पर उम्मीद जताई कि एमओयू से आई.एम.टी. गाजियाबाद के स्पोर्ट्स रिसर्च सेन्टर की मदद से हमारे विश्वविद्यालयों द्वारा राजस्थान में स्थानीय और पारम्परिक खेलों को पुनर्जीवित करने और खेलों के विकास का बेहतर वातावरण बन सकेगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का खेलों से जुड़ाव जन जागरुकता के माध्यम से ही हो सकता है। आई.एम.टी. गाजियाबाद और हमारे विश्वविद्यालयों का इस संबंध में संयुक्त प्रयास लोगों में खेल के प्रति जागरुकता पैदा कर उन्हें पारम्परिक खेलों के साथ आधुनिक खेलों से जोड़कर राजस्थान को खेलों में अग्रणी कर सकेगा।

इस अवसर पर आई.एम.टी. गाजियाबाद के स्पोर्ट्स रिसर्च सेन्टर के हैड डॉ. कनिष्क पाण्डेय ने बताया कि एमओयू के तहत प्रदेश के उदयपुर, भीलवाड़ा, डूँगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, सिरोही, बाँसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में पारम्परिक खेलों के विकास के साथ ही यहां पर खेलों से जुड़ी अन्य संभावनाओं पर कार्य करते हुए स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया जा सकेगा।

एमओयू के दौरान राज्यपाल के प्रमुख सविच श्री सुबीर कुमार, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्द राम जायसवाल, गोविन्द गुरू जनजातीय एवं मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आई.वी. त्रिवेदी, आई.एम.टी. गाजियाबाद के डायरेक्टर डॉ. विशाल तलवार, सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे।

राजस्थान सरपंच संघ का आंदोलन हुआ खत्म

जयपुर, (का.प्र.)। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर राजस्थान सरपंच संघ और ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है। सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद मीना के साथ बैठक में मांगो को लेकर सहमति बनी। इसके बाद राजस्थान सरपंच संघ के अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल और ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की है। आंदोलन समाप्ति के बाद सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों ने मंत्री मीना का माला पहनाकर स्वागत किया गया और मंत्री धन्यवाद दिया। सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा सरकार के साथ सभी मांगों पर सहमति बन गयी है। इसके बाद बुधवार से सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी काम पर लौटेंगे। इस दौरान मंत्री मीना ने कहा कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों की सरकार की ओर से सभी मांगे पर सहमति बन गयी है।

25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले

जयपुर। राज्य सरकार ने मंगलवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के 25 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिन में कानून व्यवस्था की समीक्षा की।

इसके बाद शाम को आरपीएस के तबादले कर दिए गए। आदेश के अनुसार सुरेश जैफ को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली, हिम्मत सिंह को कांमा भरतपुर, हिमांशु शर्मा को सवाईमाधोपुर, सतनाम सिंह को श्रीगंगानगर, अर्जुन सिंह शेखावत को चित्तौड़गढ़, अखिलेश शर्मा को फलौदी, प्रकाश चंद को गंगापुर सिटी, सुरेश खींची को अलवर ठामीण, भवानी सिंह राठौड़ को टोंक, नितेश आर्य को पोकरण, सिद्धान्त शर्मा को हिण्डौन, महमूद खां को जयपुर रेंज, पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी को डिप्टी कमाण्डेंट, 8 वीं बटालियन आरएसी दिल्ली, लगाया गया हैं। राजेश मील को सीआईडी विशेष शाखा मुख्यालय तृतीय जयपुर, मनोज चौधरी को एसओजी जयपुर, भोपाल सिंह लखावत को सीआईडी सीबी रेंज सैल कोटा, श्रीमनलाल मीणा को महिला अपराध अनुसंधान सैल टोंक, जयपाल सिंह को एसओजी, मुख्यालय नई दिल्ली, नरेन्द्र चौधरी को महिला अपराध अनुसंधान जालौर, नारायण लाल शर्मा को महिला अपराध अनुसंधान सैल पूर्व जयपुर, हर्ष रतनू को महिला अपराध अनुसंधान सैल सीकर, रामकल्याण मीणा को कोटा शहर, कृष्ण चंद यादव को महिला अपराध अनुसंधान सैल सवाईमाधोपुर, राकेश कुमार राजौर को लीव रिजर्व आयुक्तालय जयपुर और कैलाश सिंह सांदू को जैसलमेर लगाया गया हैं।

पीडब्ल्यूसी की बैठक में सोलह करोड़ रूपये स्वीकृत किये

जयपुर, (कासं)। जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को जेडीए (जयपुर विकास प्राधिकरण) के मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 16 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये। बैठक में जोन-13

- **जेडीए के मंथन सभागार में पीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित**

क्षेत्राधिकार में नांगल पुरोहितान आईटी सेंटर से प्रेम नगर बुरथल तक सड़क नवीनीकरण हेतु 2.39 करोड़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

सोडाला एलिवेटेड रोड के सौंदर्यीकरण हेतु फसाड लाईटिंग कार्य हेतु 2.25 करोड रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। जोन-01 में नगर निगम क्षेत्राधिकार स्थित 60 फीट सडक नवीनीकरण हेतु 5.88 करोड रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

बैठक में जोन-पीआरएन दक्षिण क्षेत्र में सेक्टर रोड पर पाईप लाईन बिछाने के लिए पीएचईडी द्वारा किये गये रोड कट की मरम्मत हेतु 3.06 करोड रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। जोन-पीआरएन दक्षिण क्षेत्र की आंतरिक सडकों पर पाईप लाईन बिछाने के लिए पीएचईडी द्वारा किये गये रोड कट की मरम्मत हेतु 2.16 करोड रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

जयपुर विकास आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की गई।

'डॉ.अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र किया'

भाजपा मांग करती है कि कांग्रेस सरकार में जरा सी भी संवेदनशीलता है तो इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए : रामलाल शर्मा

जयपुर। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र में आशा बैरवा की प्रसव के दौरान मृत्यु पर निजी अस्पताल के डॉ. को दोषी मानते हुए डॉ. अर्चना शर्मा के खिलाफ एक एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद दूसरे दिन डॉ. अर्चना शर्मा ने आत्महत्या की। लेकिन उसके बाद राजनीति के स्तर के ऊपर अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए

- **'सुसाइड नोट की राजस्थान के बाहर की फॉरेंसिक एजेंसी से जांच कराए राज्य सरकार'**

सरकार के द्वारा जो कृत्य किए गए, उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। सरकार के दबाव में पुलिस ने जिन्हें मुलजिम बनाया, वह मृतका को न्याय दिलाने की मांग कर रहे है।

भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर लालसोट के डॉ. अर्चना शर्मा सुसाइड मामले में रामलाल शर्मा एवं प्रदेश मंत्री व पूर्व संसदीय सचिव जितेन्द्र गोठवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार के द्वारा सुसाइड नोट पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, उसमें मृतका के हस्ताक्षर मैच नहीं होते हैं, केवल एक ही अक्षर हो रहा है। जांच की निष्पक्षता पर शुरू से ही सवालिया निशान भाजपा लगाती रही है। जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है, एफआईआर में जितेन्द्र गोठवाल का नाम नहीं, न ही सुसाइड नोट में शामिल है, सरकार ने निष्पक्षता के साथ जांच नहीं की गई। शर्मा ने बताया कि यदि फॉरेंसिक जांच दिल्ली या हैदराबाद से होकर आए तो मृतका को न्याय मिलेगा, जितेंद्र गोठवाल ने उस समय भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने भी अपना परिवाद दिया कि हमें सरकार की लैब पर विश्वास नहीं है, इसकी जांच हैदराबाद से कराई जाए या दिल्ली से कराई जाए।शर्मा ने कहा कि भाजपा मांग करती है की सरकार में जरा सी भी संवेदनशीलता है तो सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराएं, सरकार इसकी जांच राजस्थान की लैब से करवाने के बजाय, हैदराबाद की या दिल्ली की लैब से जांच करें, इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा और प्रदेश मंत्री जितेन्द्र गोठवाल मंगलवार को प्रेस से रूबरू हुए।

जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि, अर्चना सुसाइड मामले के अंदर सरकार द्वारा भाजपा के लोगों को इंवॉल्व करने का षड्यंत्र रचा गया, जिससे कि उस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा था, कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी को 922 रुपये खर्च करके मैंने रेल की टिकट उनको भेजी थी, इस तरह की हरकतों पर रोक लगे और उन्होंने पूरी मनगढ़ंत कहानी जो बनाकर एफआईआर दर्ज की। जिस समय अर्चना जहां पर सुसाइड करती है वहां पर घर से 1 किलोमीटर बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है, और हमने उसी समय कहा कि यह डॉक्टर की हैंडराइटिंग नहीं है, मैंने यहां के गृह सचिव को एफएसएल रिपोर्ट के लिए पहले से ही निवेदन किया था कि मुझे राजस्थान की सरकारी लैब पर विश्वास नहीं है, मुझे लगता है कि सरकार उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार इस केस में अपनी की गई गलतियों को दबाने के लिए यह सारा षड्यंत्र रच रही है। गोठवाल ने बताया कि 302 की एफआईआर पुलिस ने की, जो डॉक्टरों के खिलाफ होती ही नहीं है, पुलिस ने सारी सूचनाएं मिलने के बाद भी सुसाइड माना, यह इस बात को अंकित करता है इस केस के और भी कई सारे तथ्य हैं, जो पुलिस के सामने आना आवश्यक है। पुलिस को, एसएचओ को, सस्पेंड करने के बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जबकि परसादी लाल मीणा ने मीडिया के समक्ष कहा कि पुलिस अगर 302 में मामला दर्ज नहीं करती तो यह हादसा नहीं होता। उसके बाद भी इस केस का इन्वेस्टिगेशन अधिकारी पब्लिकली बोलते हैं कि जो सरकार मुझे कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। सरकार ने जयपुर ग्रामीण रेंज के आईजी को एक इन्वेस्टिगेशन टीम में गठित किया और केस के अंदर उन्होंने भाजपा के लोगों को फंसाया।

फीस जमा नहीं कराने पर बच्चों को लाइब्रेरी में बंद किया

जयपुर, (कासं)। जयपुर के सुबोध पब्लिक स्कूल में फीस जमा नहीं कराने पर स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में बंद करने का मामला सामने आया है। मंगलवार को 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स को 4 घंटे तक स्कूल की लाइब्रेरी में रखा गया। जैसे ही इसकी जानकारी पेरेंट्स को मिली वह स्कूल पहुंचे। विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी से बाहर निकाला।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबोध पब्लिक स्कूल के क्लास 8 से 12 के स्टूडेंट्स को फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद लाइब्रेरी में बुलाया गया था। इसके बाद 40 स्टूडेंट को बेसमेंट की लाइब्रेरी में ही 8 पीरियड तक लगभग 4 घंटे (सुबह 10 से 2 बजे) तक रखा। पेरेंट्स का आरोप है कि इस दौरान स्टूडेंट्स को न तो बाहर वॉशरूम के लिए जाने दिया गया और न ही उन्हें खाना खाने की परमिशन दी गई। इसके बाद वहां मौजूद कुछ स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को मोबाइल से इसकी जानकारी दी। बाद पुलिस के साथ पेरेंट्स स्कूल पहुंचे और बच्चों को लाइब्रेरी से बाहर निकाला।

अभिभावक एकता संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विजयवर्गीय ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस जमा नहीं कराने वाले स्टूडेंट्स को पिछले कुछ वक्त से मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं आज उन्हें लाइब्रेरी में कैद कर लिया गया। जो पूरी तरह गलत है ऐसे में शिक्षा विभाग को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया। तो मजबूरन अभिभावकों को सड़क पर उतर विरोध करना पड़ेगा।

वहीं सुबोध पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल कमलजीत यादव ने बताया कि पेरेंट्स द्वारा झूठे आरोप लगाकर स्कूल प्रबंधन पर दबाव बनाया जा रहा है। हमारे स्कूल में किसी भी स्टूडेंट्स को फीस जमा नहीं कराने की वजह से बंद नहीं किया गया है। जो वीडियो वायरल हो रहा है। उसे भी गलत तरीके से शूट कर वायरल किया जा रहा है। जो पूरी तरह गलत है। पैरंट्स ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन की ओर से फीस जमा नहीं होने की वजह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है। बीते 2 सालों की फीस दी गई है। बस पिछले 6 महीनों की फीस ही बकाया है। उन्होंने कहा कि फीस को लेकर लम्बे समय से परेशान किया जा रहा है। अभी तक बच्चों को रिजल्ट भी नहीं दिया गया। ऐसे में अब हम स्कूल के खिलाफ शिक्षा विभाग में शिकायत करेंगे।

अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मनीष विजयवर्गीय ने बताया कि मंगलवार को जयपुर के सुबोध पब्लिक स्कूल रामबाग सर्किल में अध्ययनरत कक्षा 8 से 10 तक के करीब 200 से अधिक उन विद्यार्थियों को लाइब्रेरी सहित अन्य दो तीन कमरों में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक इस मानसिक दबाव से रखा गया कि उनके अभिभावकों ने फीस जमा नहीं कराई है, बच्चों को स्पष्ट कहा गया कि जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक नियमित कक्षा में नहीं बैठने देंगे।

आंदोलन से जुड़े अभिभावक एकता आंदोलन के सदस्य नवीन शर्मा जो कि सुबोध स्कूल के अभिभावक हैं को एक विद्यार्थी द्वारा सूचित करने पर पुलिस को लेकर स्कूल पहुंचे विजयवर्गीय ने कहा कि एक तरफ सरकार बच्चों को शिक्षा के अधिकार के बारे में अपनी योजनाओं एवं प्रयासों के आंकड़े जारी कर अपने आप को विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का हितेषी सिद्ध करने का प्रयास करती रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर फीस के मामलों में अनेक निजी स्कूलों द्वारा कभी अभिभावकों को तो कभी विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार के मामले सार्वजनिक उजागर होने पर भी ऐसे स्कूलों पर कार्यवाही ना किया जाना सरकार की नीति और नियत पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है। हमने यह मामला पुलिस प्रशासन के साथ-साथ शिक्षा मंत्री, बाल संरक्षण आयोग तक पहुंचा कार्यवाही की मांग की है।